विचार बिन्दु

जो मनुष्य एक पाठशाला खोलता है वह एक जेलखाना बंद करता है। –अज्ञात

बदलता राजस्थान: शिक्षा का नया मॉडल

राजस्थान, अपनी सांस्कृतिक विरासत, रेगिस्तानी परंपराओं और विविध भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, लगातार बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्यों के बीच अब शिक्षा के नए मॉडल की ओर अग्रसर है। परंपरागत रूप से यहाँ की शिक्षा ने लोकजीवन, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण दिया है, परन्तु आज की आवश्यकता है कि वही विरासत आधुनिक शिक्षा के साथ मेल खाए ताकि युवा प्रतिभा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ स्थानीय संवेदना और पहचान को भी बनाए रखे। राजस्थान में शिक्षा का नया मॉडल इसी संतुलन का परिणाम है: एक ऐसा मॉडल जो कौशल-प्रधान, क्षेत्रीय-संवेदनशील और तकनीक-सक्षम शिक्षा को प्राथमिकता देता है, साथ ही सामाजिक समावेशन और स्थायी विकास के लक्ष्यों को केन्द्र में रखता है।

नया मॉडल स्थानीयता और ग्लोबलाइज़ेशन के बीच पुल का काम करता है। इसके मूलभूत तत्वों में पाठ्यक्रम का संदर्भीकरण, व्यावहारिक कौशलों का समावेश, बहुभाषिक शिक्षा, तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का समुचित उपयोग शामिल है। राजस्थान की ग्रामीण तथा शहरी इकाइयों में भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ हैं; इसलिए मॉडल में अनुकूलन की गुंजाइश दी गई है ताकि प्रत्येक जिला, ब्लॉक और गाँव अपनी भौगोलिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तैयार कर सकें। उदाहरण के लिए, ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में जल-संवर्धन, वैकल्पिक कृषि तकनीकें व स्थानीय हस्तशिल्प को पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सकता है, जबकि शहरी केंद्रों में आईटी, डिज़ाइन और स्टार्टअप उद्यमिता पर जोर होगा। इस तरह शिक्षा युवाओं को न केवल नौकरी की तैयारी कराती है बल्कि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने योग्य भी बनाती है।

नए मॉडल का एक प्रमुख स्तंभ कौशल आधारित शिक्षा है। पारंपरिक शैक्षणिक परिणाम जैसे अंक और डिग्रियाँ आवश्यक तो हैं परन्तु आज रोजगार बाजार में सफलता का आधार तकनीकी, संचार एवं समाधान-उन्मुख कौशल हैं। राजस्थान सरकार और निजी संस्थाएँ मिलकर वोकैशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और उद्योग-विद्यालय साझेदारियों को बढ़ावा दे रही हैं। स्कूलों में प्रारंभिक वर्ष से ही प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग तथा समकालीन कौशलों (डिजिटल साक्षरता, समस्या-समाधान, उद्यमशीलता) का समावेश किया गया है ताकि विद्यार्थी शीघ्रता से प्रयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से कार्यक्षमता विकसित कर सकें। इससे नयी पीढ़ी को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम शुरू करने की प्रेरणा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं।

शिक्षक-शक्ति का पुनरुद्धार नए मॉडल का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है। राजस्थान में शिक्षकों को सिर्फ विषय-ज्ञान नहीं बल्कि मार्गदर्शन, व्यक्तित्व-निर्माण और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दर्शाने वाले प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिक्षकों को सामुदायिक नेताओं के रूप में देखा जा रहा है वे बच्चों के साथ-साथ अभिवावकों को भी शिक्षा के महत्त्व और नवीन पद्धतियों के प्रति समेकित करते हैं। यह बदलाव शिक्षण को केवल कक्षाकक्षीय गतिविधि से निकालकर एक समुदाय-समावेशी अभियान बनाता है, जहाँ शिक्षक स्थानीय सांस्कृतिक विधाओं, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कौशलों के मध्य संपर्क स्थापित करें।

तकनीकी शिक्षा संस्थान जब कला, साहित्य व संगीत जैसे क्षेत्रों पर काम करते हैं तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि हमारी पुरातन परंपराओं का आदर करने वाली एक नई पीढ़ी सशक्त हो रही है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान और शिल्पीय कौशल के साथ सांस्कृतिक एवं कलात्मक संवेदनशीलता जोड़ने की यह दिशा नई शिक्षा नीति के मूल सिद्धांतों से मेल खाती है, जो बहुआयामी शिक्षा, क्रॉसडिसिप्लिनरी लर्निंग और स्थानीय ज्ञान के संरक्षण पर जोर देती है। महेश स्वामी जैसे विचारक और मार्गदर्शक, जिनकी सोच में परंपरा और नवाचार का संयोजन है, उन युवा मनों में जिजीविषा जगाते हैं जो तकनीक को सिर्फ उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं। जब संस्थान तकनीकी पाठ्यक्रमों में संगीत, लोककथाएँ, लोकहस्तकला और साहित्य को शामिल करते हैं, तो विद्यार्थी तकनीकी समस्याओं के समाधान में मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण लाते हैं, स्थानीय समृद्ध संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को नई विधियों से पुनर्जीवित करते हैं, और रोजगार व उद्यमशीलता के नये रास्ते खोलते हैं। नई शिक्षा नीति की भाषा में यह समावेशिता आत्मसात करना न केवल रचनात्मकता व आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसत्ता को भी मज़बूत बनाता है यानी तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक जड़ों के बीच एक जीवंत सेतु निर्मित होता है। ऐसे प्रयास न केवल विद्यार्थियों को बहुआयामी कौशल देते हैं, बल्कि समाज को भी एक ऐसी दिशा प्रदान करते हैं जहां आधुनिकता और परंपरा सहअस्तित्व में, नवोन्मेष को मानवीय अर्थ और स्थानीय प्रासंगिकता प्रदान करें।

राजस्थान का नया शिक्षा मॉडल एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो वैश्विक मानकों के साथ स्थानीय संवेदनशीलता का संयोजन करता है। यह मॉडल कौशल आधारित, बहुभाषिक, तकनीक समर्थित और सांस्कृतिक रूप से समावेशी है। यदि इसे सजीव रूप में लागू किया जाए अर्थात् नीतिगत समर्थन, समुदायिक भागीदारी और सतत निवेश के साथ तो यह न केवल शैक्षिक सुधार लाएगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।

शिक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच संबंध को मजबूती देने के लिए कैरियर मार्गदर्शन और स्थानीय-रोजगार मानचित्र बनाये गए हैं। युवा अब शहरों की ओर केवल नौकरियों की तलाश में नहीं भाग रहे; उन्हें स्थानीय पारंपरिक उद्योग, पर्यटन, और हरित अर्थव्यवस्था (जैसे जल प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा) में अवसर दिखाये जा रहे हैं। स्कूलों और स्थानीय उद्योगों के बीच समन्वय से इंटर्नशिप और छोटे व्यवसाय आरम्भ करने वाले प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इससे ग्रामीण पलायन पर नियंत्रण रहता है और स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ती है।

पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक संरक्षण का समावेश भी इस मॉडल की विशिष्टता है। राजस्थान की लोककथाएँ, लोकसंगीत, हस्तशिल्प और पर्यावरणीय जीवन-ज्ञान को सीखने के माध्यम बनाया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को अपनी जड़ें जानने का अवसर मिलता है और सांस्कृतिक पर्यटन तथा हस्तशिल्प कारोबार में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। शिक्षा अब केवल आधुनिक विज्ञान तक सीमित नहीं है; यह एक ऐसा माध्यम है जो स्थानीय पहचान को सम्मान देते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

नवोन्मेष और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों में सक्रिय प्रयोगशालाओं और इनोवेशन हब का निर्माण हो रहा है। छोटे स्तर पर स्टूडेंट-प्रोजेक्ट फंडिंग, मेकाथॉन और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। इससे छात्रों में समस्या-समाधान की प्रवृत्ति, टीम-वर्क और वास्तविक दुनिया की नौकरी योग्य क्षमताएँ विकसित होती हैं। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च को स्थानीय मुद्दों जैसे जल संकट, सूखा-प्रबंधन और पारंपरिक जल संरचनाओं की आधुनिक व्याख्या पर केंद्रित किया जा रहा है।

वित्तीय और नीतिगत समर्थन का भी विशेष प्रावधान इस मॉडल में है। शिक्षा के नवाचारों के लिए अनुदान, निजी-सरकारी भागीदारी और सीएसआर फंड का उपयोग कर विशेष परियोजनाएँ चालू की जा रही हैं। यह मॉडल केवल उपरोक्त नीतियों तक सीमित नहीं है बल्कि एक लचीला फ्रेमवर्क देता है जिसे समय-समय पर स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। सफलता का आकलन अब केवल परीक्षाफल से नहीं बल्कि व्यावसायिक सफलता, सामुदायिक परिवर्तन तथा पर्यावरणीय संकेतकों के आधार पर भी किया जाता है।

हालांकि चुनौतियाँ अभी भी कम नहीं हैं। शिक्षकों की कमी, दूरदराज़ इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी, तथा सामाजिक मान्यताएँ जो कुछ समुदायों में लड़कियों की पढ़ाई पर प्रभाव डालती हैं- ये बाधाएँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना केवल शिक्षा नीति से नहीं बल्कि समग्र सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक जागरूकता और दीर्घकालिक निवेश से किया जा सकता है। इसी कारण शिक्षा के नए मॉडल में सरकार, स्थानीय समुदाय, गैर-सरकारी संस्थाएँ और निजी क्षेत्र-सभी भागीदारों की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य मानी गई है।

राजस्थान का नया शिक्षा मॉडल एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो वैश्विक मानकों के साथ स्थानीय संवेदनशीलता का संयोजन करता है। यह मॉडल कौशल आधारित, बहुभाषिक, तकनीक समर्थित और सांस्कृतिक रूप से समावेशी है। यदि इसे सजीव रूप में लागू किया जाए अर्थात् नीतिगत समर्थन, समुदायिक भागीदारी और सतत निवेश के साथ तो यह न केवल शैक्षिक सुधार लाएगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। राजस्थान की युवा पीढ़ी, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुडी और वैश्विक क्षितिजों के लिए तैयार होगी, निश्चय ही राज्य को एक नया, सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य दे सकती है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार

यह परीक्षा है या युद्ध ?

राजेन्द्र भाणावत

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 3 मई, 2026 को आयोजित नीट परीक्षा, पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। अब यह पुनः 21 जून 2026 को आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा की तैयारी के समाचार, जिस प्रकार से मीडिया में आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि यह परीक्षा नहीं अपितु युद्ध की तैयारी हो रही है।

यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय 21 जून को होने वाले नीट की मॉनिटरिंग अपने स्तर पर कर रहा है, जबकि इसे आयोजित करने की पूरी जिम्मेदारी एन टी ए की है। एन टी ए का तो गठन ही इस प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन के लिए 2019 में किया गया था। क्या एक परीक्षा की मॉनिटरिंग के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के पास और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? पूरे देश में संचार के प्रमुख साधन 'टेलीग्राम' पर 22 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीट के प्रश्न पत्रों को विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायु सेना के वायुयानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा 200 से अधिक उड़ानें भरी गई हैं। इन पर कितना खर्चा हुआ होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की तैयारी तो स्वतंत्रता के बाद, शायद किसी भी परीक्षा के लिए नहीं की गई।

प्रश्न पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वायु सेना के विमान और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग हास्यास्पद है। क्या जाँच में कहीं पर यह सिद्ध हुआ है कि पेपर, परिवहन के दौरान लीक हुए थे? पेपर लीक की घटना को रोकने के बारे में आवश्यक प्रभावी कार्यवाही तभी संभव है जब यह पता किया जा सके कि पेपर लीक किसके स्तर पर हुआ? मजे की बात तो यह है कि एन टी ए तो पेपर लीक होना ही नहीं मान रहा है। फिर क्यों पहली परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई जा रही है? क्या यह 22 लाख छात्रों के साथ मजाक नहीं है? नीट के पेपर, 2024 में भी लीक हुए थे और कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। आज वे सभी जमानत पर हैं और शायद पुनः उसी काम में लग गए होंगे। इसी प्रकार 2025 के नीट पेपर भी लीक हुए थे लेकिन उसके ज्यादा समाचार नहीं आए। बाद में पता लगा कि कुछ व्यक्तियों को पेपर मिले थे और उसके आधार पर, अयोग्य होते हुए भी उनका चयन हो गया था। आज वे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं।

पेपर लीक की घटनाएं बार-बार होने का प्रमुख कारण ही यह है कि इसके कारणों का सही पता नहीं लगाया जाता। इसी कारण, इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। पेपर लीक गंभीर अपराध है और उसके साथ विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा है फिर भी इसमें लिप्त लोगों पर कठोर कार्यवाही न होना सरकारी संवेदनहीनता का ही द्योतक है। एक व्यक्ति की हत्या के लिए हत्यारे को आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है। नीट के पेपर लीक के कारण हुई लगभग 20 विद्यार्थियों की आत्महत्या की जिम्मेदारी एन टी ए के अधिकारियों की क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? सरकार द्वारा ऐसा कुछ करना तो दूर, उसके शिक्षा मंत्री तक को अब तक पद से नहीं हटाया गया है,जबकि इस बारे में आंदोलन लगातार चल रहा है।

केंद्र सरकार, परीक्षा आयोजन को भी एक इवेंट बना रही है। 'टेलीग्राम' बंद करना,वायु सेना के माध्यम से पेपर पहुँचाना और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग तथा इसे मीडिया में प्रमुखता से प्रचारित, प्रसारित करना इवेंट आयोजन जैसा ही तो है। समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर वायुसेना के विमानों द्वारा प्रश्न पत्र ले जाने के फोटो प्रकाशित करना भी इसी का हिस्सा है।

नीट जैसी परीक्षा के पेपर कई व्यक्ति मिलकर तैयार करते हैं किंतु अंतिम प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न होंगे, इसकी जानकारी एन टी ए के ही कुछ अधिकारियों को होती है। एनटीए के अध्यक्ष अभी तक वही बने हुए हैं और पूर्व महानिदेशक को प्रमोशन देकर कहीं और लगा दिया गया है। इसे जवाबदेही का पूर्णतया अभाव ही कहा जाएगा।

वायुसेना के माध्यम से पेपर भेजने का निर्णय कुछ कुछ वैसा ही है, जैसे पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो किंतु बिना यह पता लगाए कि लीकेज कहां पर है, उसे ठीक करने का प्रयास किया जाय। गाड़ी के पहिए का पंक्चर होने पर, पहले ठीक करने वाला पानी डालकर यह देखता है कि कहां से पानी के बुलबुले निकल रहे हैं ताकि वह पता लगा सके कि पंचर कहां हुआ है? और फिर, वह उसे मरम्मत करने का कार्य करता है। इतनी साधारण सी बात भी सरकार, नीट की परीक्षा के संबंध में नहीं समझ पा रही है। ऐसा लगता है वह केवल अंधेरे में तीर चला रही है और इसे भी अपने प्रचार का माध्यम बना रही है।

देश में प्रतिवर्ष विभिन्न हजारों परीक्षाओं के लाखों प्रश्न पत्र होते हैं जिनमें करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं। इस प्रकार से वायु सेना का उपयोग यदि प्रश्न पत्र ले जाने के लिए किया गया तो कितनी परीक्षाओं में ऐसा किया जा सकेगा? छात्र के लिए प्रत्येक परीक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उपयुक्त विश्वसनीय व्यक्तियों को परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में लगाया जाए। उनकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का संदेह न हो। विमानों द्वारा प्रश्न पत्र ले जाना किसी पेड़ के पत्तों को तोड़ने जैसा है जिसका कोई लाभ नहीं है। समस्या हल करने के लिए समस्या की जड़ पर प्रहार करना आवश्यक है।

सार्वजनिक रूप से सरकार को यह बताना चाहिए कि 2024 में प्रश्न पत्र लीक करने के लिए जिम्मेदार कौन थे और उन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई? इसी प्रकार नीट 2026 के लिए यह बताना आवश्यक है कि किस स्तर पर पेपर लीक हुए? एन टी ए अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के अपने पद पर बने रहते हुए इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी, यह संभव नहीं है। टेलीग्राम जैसे प्रमुख संचार माध्यम को प्रतिबंधित करना युद्ध के समय उठाए गए कदम जैसा है। इस कारण लाखों लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार जब भी इंटरनेट की सेवा प्रतिबंधित करती है तो पूरे क्षेत्र में किस प्रकार सामान्य गतिविधियां ठप्प हो जाती हैं, इसका अंदाजा नागरिकों को है। केवल परीक्षा आयोजन के लिए टेलीग्राम जैसे महत्वपूर्ण साधन को प्रतिबंधित कर देना नितांत अनुचित है। सरकार को शायद इस बात का भी पता है कि आज के युवा पेपर लीक के कई वैकल्पिक तरीके अपना सकते हैं। तो फिर, इस प्रतिबंध का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। जैसे मोबाइल इंटरनेट को बंद करने पर, वाई-फाई तो चालू रहता ही है। मोबाइल इंटरनेट को बंद करने से परेशानी होती है किंतु इसका कोई विशेष लाभ प्रतिबंध लगाने वालों को नहीं होता है। टेलीग्राम कंपनी, प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में गई अवश्य है किंतु अब तक उसे कोई राहत नहीं मिली है। टेलीग्राम को पूरे देश में बंद करना लगभग वैसा ही है जैसे यदि सड़क पर एक एक्सीडेंट हो, तो सड़कों का उपयोग ही बंद कर दिया जाए अथवा किसी के बालों में जूं पड़ जाए तो पूरा सिर ही काट दिया जाए।

यदि प्रधानमंत्री कार्यालय एक परीक्षा की निगरानी जैसे रूटीन के काम में लग जाएगा तो देश का संचालन कौन करेगा? जो काम बिल्कुल साधारण प्रकृति का है उसे इतना बढ़ा-चढ़ा कर बता दिया गया है जैसे परीक्षा कराना असंभव सा कार्य हो गया है। हमारे पड़ोसी देश चीन में लगभग 1-2 करोड़ विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठते हैं और वहां गत 20 सालों में कोई पेपर कभी लीक नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है, वहां डर इतना है कि एक बार इस प्रकार की घटना होने पर संबंधित व्यक्तियों को फांसी तक हो सकती है।

नीट की परीक्षा दुबारा कराने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें मीडिया में तो बहुत स्थान मिल सकता है, किंतु यह नीट की परीक्षा कराने का कोई सही तरीका नहीं कहा जा सकता। यह परिपाटी उचित भी नहीं है। जिसका जो काम है, वह उसे सही तरह करे, यह आवश्यक है। एन टी ए और शिक्षा मंत्रालय का काम यदि प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा तो फिर शिक्षा मंत्रालय की आवश्यकता ही क्या है?

नीट के पेपर आउट होने पर कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है और अनेक छात्र मानसिक अवसाद में चले गए हैं। उसे देखते हुए, पूरी शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर ही पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्यों किसी विद्यार्थी के भविष्य का निर्धारण केवल 3 घंटे की परीक्षा से कर दिया जाता है? क्या उन्हें विभिन्न प्रकार के अन्य वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार विचार नहीं कर सकती ताकि वह जीवन के अमूल्य तीन-चार वर्ष केवल एक परीक्षा पर न लगा दें, और उसमें असफल होने पर अपने जीवन का अंत ही कर लें? जीवन अमूल्य है और इसकी रक्षा करना सर्वोपरि प्राथमिकता है, परिवार के लिए भी और सरकार के लिए भी।

आशा है सरकार परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही शिक्षा और रोजगार की पूरी व्यवस्था पर गंभीरता से पुनरावलोकन करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी ताकि जिस प्रकार की स्थिति नीट परीक्षा के पेपर आउट होने से हुई है वैसी स्थिति देश में उत्पन्न न हो और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होने से बच सके।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

क्या भारत भविष्य के 'वाटर इमरजेंसी' की ओर बढ़ रहा है?

राम शर्मा

जल जीवन का आधार है। मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ और आज भी किसी देश की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार उसके जल संसाधन हैं। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया जिस सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें जल संकट प्रमुख है। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। देश की बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने जल संकट को गंभीर बना दिया है। आज यह प्रश्न प्रासंगिक हो गया है कि क्या भारत भविष्य में किसी 'वाटर इमरजेंसी' की ओर बढ़ रहा है?

भारत विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी का घर है, जबकि उसके पास विश्व के केवल 4 प्रतिशत मीठे जल संसाधन हैं। यह असंतुलन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगीकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ी है, लेकिन जल संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता तेजी से घट रही है।

देश के अनेक शहर पहले ही जल संकट की गंभीर स्थिति का सामना कर चुके हैं। कुछ वर्ष पहले दक्षिण भारत के प्रमुख महानगरों में से एक, बंगलुरू को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ा था। कई इलाकों में टैंकरों के सहारे पानी की आपूर्ति करनी पड़ी। इसी प्रकार चेन्नई, दिल्ली और अन्य महानगरों में भी समय-समय पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती रही है। यह संकेत है कि समस्या अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी भारत भी इसकी चपेट में आ रहा है। जल संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना जाता है। कृषि, घरेलू उपयोग और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों ट्यूबवेल और बोरवेल लगातार जमीन से पानी निकाल रहे हैं। कई राज्यों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर वर्ष दर वर्ष गिरता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और जटिल बना दिया है। पहले जहां मानसून अपेक्षाकृत नियमित रहता था, वहीं अब वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की भारी बारिश पूरे वर्ष की औसत वर्षा को पूरा कर देती है, लेकिन उसका अधिकांश जल बहकर समुद्र में चला जाता है। इससे भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और जल संकट गहराता है।

भारत में जल प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था भी चिंता का विषय है। आज भी वर्षा जल का बड़ा हिस्सा संरक्षित नहीं किया जाता। जल संरक्षण की योजनाएं कई बार कागजों तक सीमित रह जाती हैं। शहरों में तालाब, झीलें और पारंपरिक जल स्त्रोत लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। जिन जलाशयों ने सदियों तक समाज की जल आवश्यकताओं को पूरा किया, वे अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। कृषि क्षेत्र में भी जल का उपयोग अत्यधिक और कई बार अनियोजित तरीके से होता है। भारत में उपलब्ध मीठे जल का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा कृषि में उपयोग किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान और गन्ने जैसी फसलों की खेती भूजल पर भारी दबाव डालती है। यदि कृषि पद्धतियों में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है।

शहरीकरण भी जल संकट को बढ़ा रहा है। तेजी से फैलते शहरों में कंक्रीट का विस्तार हो रहा है, जिससे वर्षा जल जमीन में समाहित नहीं हो पाता। इसके अलावा पाइपलाइन लीकेज और खराब वितरण प्रणाली के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है। कई शहरों में प्रतिदिन लाखों लीटर पानी रिसाव के कारण नष्ट हो जाता है। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब लाखों लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता। जल संकट का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी, उद्योगों की उत्पादन क्षमता पर असर और ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। जल की कमी से खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त पानी को लेकर सामाजिक तनाव और क्षेत्रीय विवाद भी बढ़ सकते हैं।

हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान और चरम मौसमीय घटनाओं ने जल संकट को और गंभीर बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दशकों में जल की उपलब्धता भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन सकती है। यह स्थिति केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप भी ले सकती है। हालांकि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। भारत के पास इस चुनौती से निपटने के पर्याप्त अवसर भी हैं। सबसे पहले जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना होगा। वर्षा जल संचयन को प्रत्येक घर, विद्यालय, उद्योग और सरकारी भवन में अनिवार्य बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास आवश्यक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों, बावड़ियों और पारंपरिक जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना होगा। इससे पानी की बचत होगी और कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित करना भी समय की आवश्यकता है। साथ ही जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। शहरी क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना होगा। विकसित देशों की तरह उपचारित जल का उपयोग उद्योगों, उद्यानों और अन्य गैर-पेय कार्यों में किया जा सकता है। इससे मीठे जल पर दबाव कम होगा। साथ ही नगर निकायों को जल वितरण प्रणाली में सुधार कर रिसाव को न्यूनतम करना होगा।

अंततः यह स्पष्ट है कि भारत जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है और यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहीं तो भविष्य में 'वाटर इमरजेंसी' जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यह संकट अपरिहार्य नहीं है। दूरदर्शी नीतियों, प्रभावी जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और जनभागीदारी के माध्यम से इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। जल संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानने के बजाय प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाना होगा। यदि आज हम पानी की प्रत्येक बूंद का महत्व समझ लें, तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट की भयावह स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल है तो कल है, और भारत का भविष्य भी जल सुरक्षा पर ही निर्भर करता है।

–राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

ग्रामीण सेवा शिविर बना जनकल्याण का केंद्र

■ मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से कोयली देवी व बर्फी देवी को मिली राहत

पावटा, (निसं)। पावटा तहसील के ग्राम प्रेमनगर एवं ब्लॉक विराटनगर की ग्राम पंचायत छीतोली में शुक्रवार को आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर का आयोजन विधायक कुलदीप धनकड़ के मुख्य आतिथ्य एवं विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार व पावटा उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा के निर्देशन में हुआ।

शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान किया तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत छीतोली में कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में सफलता की कहानी लिखते हुए ग्राम जादू का बास निवासी कोयली देवी पत्नी महेश गुर्जर को ग्रामीण सेवा शिविर में मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के तहत निःशुल्क बीमा पॉलिसी प्रदान की गई। कोयली देवी ने बताया कि पहले पशुओं का बीमा कराने के लिए भारी प्रीमियम राशि जमा करवानी पड़ती थी, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार की इस योजना से उन्हें बिना किसी शुल्क के बीमा सुविधा मिली है। उन्होंने सरकार एवं पशुपालन विभाग का आभार जताते हुए अन्य पशुपालकों से भी योजना का लाभ लेने की अपील की।

वहीं पावटा तहसील के ग्राम प्रेमनगर निवासी बर्फी देवी की कहानी भी सरकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाती है। बर्फी देवी के लिए पशुपालन आजीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन पहले पशुओं के बीमार होने और उपचार पर होने वाले खर्च से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा होने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिला। इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोयली देवी और बर्फी देवी जैसी सफलता की कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलने पर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 20 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (शुद्ध), शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2083, मघा नक्षत्र प्रातः 9:26 तक, वज्र योग दिन 12:48 तक, तैतिल करण दिन 3:47 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 9:26 तक है। आज अरण्य षष्ठि व्रत, विन्ध्यवासिनी पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:20 से 9:03 तक, चर 12:28 से 2:11 तक, लाभ अमृत 2:11 से 5:36 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:19

मेष

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह

मानसिक तनाव दूर होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। आजल घर-परिवार में अनावश्यक धन खर्च होगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

तुला

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

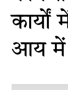

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मकर

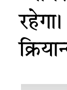

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ

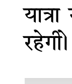

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।